



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 वैशाख 1939 (श0)

(सं0 पटना 354) पटना, मंगलवार, 2 मई 2017

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

2 मार्च 2017

सं0 22 नि0 सि0 (मुक0)—जम0—19—36/2009/331—श्री बिन्देश्वरी चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गालूडीह (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को मे0 डी0 के0 रोड लाईन्स, संवेदक द्वारा जाली बैंक गारण्टी दाखिल किये जाने और इन जाली बैंक गारंटियों के विरुद्ध 14,50,000/— रुपये (चौदह लाख पचास हजार रुपये) मात्र का अनसिक्योर्ड अग्रिम उपलब्ध कराने, अधीक्षण अभियंता के आदेश का उल्लंघन करने एवं कदाचारों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के उपरान्त विभागीय आदेश सं0 100 दिनांक 04.04.91 द्वारा निलंबित किया गया जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में CWJC सं0 4439/94 दायर किया गया। उक्त याचिका में पारित न्याय—निर्णय के अनुपालन में श्री चौधरी का निलंबन आदेश निरस्त कर दिया गया एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश सं0 292 दिनांक 18.06.93 सह—पठित ज्ञापांक 1474 दिनांक 18.06.92 द्वारा निम्नांकित दण्ड संसूचित किया गया:—

(1) निन्दन की सजा आरोप वर्ष 1989—90

(2) तीन वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

उपरोक्त विभागीय आदेश के विरुद्ध चौधरी द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 942/94 दायर की गई जिसमें दिनांक 23.03.95 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा न्याय—निर्णय पारित करते हुए विभागीय आदेश सं0 292 दिनांक 18.06.93 द्वारा संसूचित दण्डों में से निन्दन की सजा को बरकरार रखा गया लेकिन संचयात्मक प्रभाव से वेतनवृद्धि को रोकने के आदेश को रद्द कर दिया गया। उक्त न्याय—निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय का यह भी निर्देश था कि वादी के विरुद्ध नये सिरे से कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र है। तदनुसार विभागीय संकल्प सं0 651 दिनांक 20.05.95 द्वारा उनके विरुद्ध गठित आरोप के संबंध में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री चौधरी के विरुद्ध मे0 डी0 के0 रोड लाईन्स, संवेदक को गलत बैंक गारण्टी (फर्जी) रहने के बावजूद इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को नहीं देने, संवेदक को 14,34,725/— रुपये का गलत बैंक गारण्टी रहने के बावजूद भुगतान करने का आरोप प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। विभागीय पत्रांक 2630 दिनांक 23.11.96 द्वारा श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी और आरोप सही पाया गया। सेवा बर्खास्तगी के निर्णय पर बिहार

लोक सेवा आयोग एवं मंत्रिमण्डल की सहमति प्राप्त की गई। चूंकि श्री चौधरी दिनांक 31.01.97 को सेवानिवृत्त हो गये, इसलिए सेवा बर्खास्तगी का दण्ड संसूचित नहीं हो पाया।

मामले के पूर्ण समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश सं० 1122 दिनांक 24.09.97 सह-पठित ज्ञापांक 3113 दिनांक 24.09.97 द्वारा सेवा बर्खास्तगी के समतुल्य बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी०) के तहत निम्न दण्ड संसूचित किया गया।

(1) शत प्रतिशत पेंशन एवं उपादान पर सदा के लिए रोक।

उपरोक्त विभागीय आदेश के विरुद्ध श्री चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC सं० 11788/97, बिन्देश्वरी चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दायर किया गया, जिसमें दिनांक 04.12.98 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय-निर्णय पारित करते हुए उक्त याचिका को निरस्त (डिसमिस) कर दिया गया। श्री चौधरी द्वारा उक्त न्याय-निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल० पी० ए० सं० 436/2000, बिन्देश्वरी चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दायर किया गया, जिसमें दिनांक 20.05.08 को न्याय-निर्णय पारित करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उक्त एल० पी० ए० को निरस्त (डिसमिस) करते हुए निर्णय पारित किया गया कि वादी श्री चौधरी के जीवन के अंतिम क्षण में शत प्रतिशत पेंशन एवं ग्रेच्युटी रोकने का दण्ड बहुत कष्टकर है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को श्री चौधरी को 50 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत ग्रेच्युटी देने के संबंध में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

उक्त न्यायादेश के आलोक में सरकार के स्तर पर मामले की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त उक्त एल० पी० ए० में पारित न्याय-निर्णय का अनुपालन करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार श्री चौधरी को पूर्व में संसूचित दण्ड को संशोधित करते हुए शत प्रतिशत पेंशन एवं उपादान सदा के लिए रोकने के दण्ड की जगह 50 (पचास) प्रतिशत पेंशन एवं उपादान रोकने का दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

वर्णित स्थिति में एल० पी० ए० सं० 436/2000 में पारित न्याय-निर्णय के अनुपालन करते हुए श्री बिन्देश्वरी चौधरी, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता को विभागीय आदेश सं० 1122 दिनांक 24.09.97 द्वारा संसूचित दण्डादेश को संशोधित करते हुए शत प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक की जगह निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है:-

(1) 50 (पचास) प्रतिशत पेंशन एवं 50 (पचास) प्रतिशत उपादान पर सदा के लिए रोक।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल० पी० ए० सं० 436/2000 में पारित आदेश के विरुद्ध श्री बिन्देश्वरी चौधरी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस० एल० पी० सं० 10529/09 जो सिविल अपील सं० 3929/2011 में परिवर्तित है, दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को न्याय-निर्णय पारित करते हुए दिनांक 24.09.97 एवं 17.06.98 द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा श्री बिन्देश्वरी चौधरी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गालूडीह (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड "50 (पचास) प्रतिशत पेंशन एवं 50 प्रतिशत उपादान पर रोक" को निरस्त किया जाता है एवं निलंबन अवधि दिनांक 04.04.91 से 17.06.93 को कर्तव्य अवधि मानते हुए शेष वेतनादि भुगतान करने का निर्णय लिया जाता है।

उक्त निर्णय श्री बिन्देश्वरी चौधरी, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 354-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>